भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-104
उत्तर देने की तारीख-08.12.2025

पीएम-श्री योजना के अंतर्गत विद्यालयों का उन्नयन

†*__104. डॉ. कडियम काव्य:__

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) पीएम-श्री योजना के अंतर्गत वारंगल में काकतीय विश्वविद्यालय और सरकारी विद्यालयों के उन्नयन की स्थिति का ब्यौरा क्या है;
(ख) वर्ष 2023-24 के दौरान वारंगल जिले में माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले छात्रों की संख्या कितनी है; और
(ग) सरकार द्वारा वारंगल से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और छात्रावास सुविधाएं प्रदान करने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
शिक्षा मंत्री
(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (ग): विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है।

****

'पीएम-श्री योजना के अंतर्गत विद्यालयों का उन्नयन' के संबंध में माननीय संसद सदस्य डॉ. कडियम काव्य द्वारा दिनांक 08.12.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 104 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): चूंकि शिक्षा समवर्ती सूची में है, अत: शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करना केन्द्र और राज्य सरकारों दोनों की जिम्मेदारी है। तथापि, केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित की हैं।

उच्चतर शिक्षा विभाग राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) कार्यान्वित कर रहा है जो एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है और जिसका उद्देश्य विशिष्ट राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को निधि प्रदान करना है ताकि निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप उनकी गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके। सरकार ने जून 2023 में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) के रूप में रूसा का तीसरा चरण शुरू किया है, जिसका परिव्यय 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए 12926.10 करोड़ रुपये है ताकि शैक्षिक रूप से असेवित/वंचित क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। पीएम-उषा के अंतर्गत, विश्वविद्यालयों के उन्नयन के लिए कोई विशिष्ट घटक नहीं है। तथापि, काकतीय विश्वविद्यालय को रूसा के तहत, अनुसंधान केंद्रों, उद्यमिता, रोजगार क्षमता और नवाचार केंद्रों के निर्माण और विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं के संचालन के लिए कुल 50 करोड़ रुपये की राशि की सहायता 'अनुसंधान नवाचार और गुणवत्ता सुधार' घटक के तहत प्रदान की गई है।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम श्री) लागू कर रहा है, जो एक केंद्र प्रायोजित योजना है और जिसमें केंद्र सरकार/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित स्कूलों में से मौजूदा स्कूलों को मजबूत करके पीएम श्री स्कूल स्थापित किए जाते हैं। इन स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की सभी पहलों का प्रदर्शन करना है, आदर्श स्कूल बनना है, और आसपास के अन्य स्कूलों के लिए बेंचमार्किंग नेतृत्व भी प्रदान करना है।

पीएम-श्री योजना के तहत, तेलंगाना के वारंगल जिले से कुल 16 स्कूलों को पीएम श्री के रूप में स्तरोन्नत किया गया है। चयनित स्कूलों की सूची https://pmshri.education.gov.in/state लिंक पर देखी जा सकती है।

(ख): स्कूल छोड़ने की दर किसी निश्चित स्कूल वर्ष में किसी निर्धारित स्तर पर नामांकित समूह के विद्यार्थियों का अनुपात है, जो अब अगले स्कूल वर्ष में किसी भी ग्रेड में नामांकित नहीं हैं। छात्रों के नामांकन से संबंधित डेटा https://dashboard.udiseplus.gov.in लिंक पर देखा जा सकता है। तेलंगाना राज्य द्वारा दी की गई जानकारी के अनुसार, यूडीआईएसई+ 2023-24 के अनुसार माध्यमिक स्तर पर तेलंगाना के वारंगल जिले में स्कूल छोड़ने की दर 22.45 है।

(ग): उच्चतर शिक्षा विभाग और इसके स्वायत्त निकाय, अर्थात् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) तेलंगाना के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति सहित उच्च शिक्षा के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं लागू करते हैं।

यह विभाग कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (पीएम-यूएसपी) केंद्रीय क्षेत्र की छात्रवृत्ति योजना (2008 में शुरू की गई) का कार्यान्वयन कर रहा है। वर्ष 2024-25 में तेलंगाना राज्य को छात्रवृत्ति के रूप में वारंगल जिले में कुल 136 लाभार्थियों के लिए 0.19 करोड़ रुपये सहित 7.5 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता वितरित की गई है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) वित्तीय सहायता प्रदान करके उच्चतर अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना भी कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत, वर्ष 2024-25 में तेलंगाना राज्य को छात्रवृत्ति के रूप में वारंगल जिले के कुल 8 लाभार्थियों के लिए 0.12 करोड़ रुपये सहित 11.67 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) एआईसीटीई प्रगति छात्रवृत्ति योजना (डिग्री और डिप्लोमा), एआईसीटीई स्वनाथ छात्रवृत्ति योजना (डिग्री और डिप्लोमा), एआईसीटीई सक्षम छात्रवृत्ति योजना (डिग्री और डिप्लोमा), एआईसीटीई पीजी छात्रवृत्ति योजना, एआईसीटीई डॉक्टोरल फैलोशिप (एडीएफ) जैसी विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं को भी कार्यान्वित कर रही है। इन योजनाओं के अंतर्गत, छात्रवृत्ति के रूप में कुल 3013 लाभार्थियों के लिए वर्ष 2024-25 में तेलंगाना राज्य को 19.6 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय वर्ष 2021-22 से एक केंद्र प्रायोजित योजना, प्रधानमंत्री अनुसुचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-एजेएवाई) को लागू कर रहा है। इस योजना के तीन घटक हैं नामत: (i) 'आदर्श ग्राम', (ii) 'अनुसूचित जाति (एससी) समुदायों की सामाजिक-आर्थिक बेहतरी के लिए जिला/राज्य स्तरीय परियोजनाओं के लिए अनुदान सहायता और (iii) 'छात्रावास'। छात्रावास घटक के अंतर्गत, छात्रावासों का निर्माण अनुसूचित जातियों (एससी) से संबंधित छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाने और प्रोत्साहित करने के साधनों में से एक है। इस योजना के तहत, तेलंगाना राज्य में 11 छात्रावास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 2 छात्रावास (150 बालकों की क्षमता वाला 1 और 300 बालिकाओं की क्षमता वाला 1) काकतीय विश्वविद्यालय, वारंगल के लिए कुल 9 करोड़ रुपये की राशि के लिए स्वीकृत किए गए हैं।

पीएम-उषा के तहत, तेलंगाना के वारंगल जिले को काकतीय विश्वविद्यालय और काकतीय डिग्री कॉलेज (एम) के 2 कॉलेजों, हनमकोंडा और पिंगले गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज (डब्ल्यू), वाडेपल्ली में कुल 56 करोड़ रुपये की राशि सहायता को मंजूरी दी गई है। इस योजना के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उच्चतर शिक्षा में पहुंच और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए आवश्यक छात्रावासों, शैक्षिक और प्रशासनिक भवनों, प्रयोगशालाओं और अन्य सुविधाओं के निर्माण सहित अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

****